वर्ष 1 अंक 6 जून 1979 50 पैसे

सीटू मजदूर

सी. आई. टी. यू. का मासिक मुखपत्र

सभी ट्रेड यूनियनों का संयुक्त मंच बनाने के लिए सीटू का आह्वान

अप्रैल 79 में मद्रास में संपन्न सीटू के चौथे सम्मेलन के फैसले के मुताबिक सीटू के जनरल सेक्रेटरी कामरेड राममूर्ति ने "मजदूर वर्ग तथा कर्मचारियों के संयुक्त संघर्ष को व्यापक तथा मजबूत बनाने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के मुख्य मुद्दों पर आपसी विचार-विमर्श के लिए एक प्रभावी मंच का काम करने वाले एक कनफैडरेशन के गठन का प्रस्ताव करते हुए देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा 41 इंडस्ट्रियल फेडरेशनों को पत्र लिखा है.

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में यू. टी. यू. सी., एच. एम. एस., इंटक एटक, बी. एम. एस., टी. यू. सी. सी., एन. एल. ओ. आदि शामिल हैं.

सीटू के चौथे सम्मेलन में सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने अपने भाषण में इसी तरह के कनफैडरेशन, या कम से कम समस्त राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों और इंडस्ट्रियल फेडरेशनों की श्रमिक समन्वय कमेटी के गठन की बात की थी—जिससे आम सहमति तथा एकमत से फैसले किये जा सकें.

सीटू के चौथे सम्मेलन में इस संदर्भ में एक प्रस्ताव भी पास किया गया था जिसमें संयुक्त आंदोलन का निर्माण करने के लिए ट्रेड यूनियनों की संयुक्त परिषद (यू. सी. टी. यू.) जैसे संगठन के गठन का सुझाव दिया गया था, और प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि "सीटू दूसरे संगठनों से हर मुमकिन सहयोग करेगी ताकि मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करने वाली एकता का निर्माण हो सके."

जबकि राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों तथा औद्योगिक फेडरेशनों के जवाबों की प्रतीक्षा है. उम्मीद की जाती है कि इस प्रस्ताव को पर्याप्त समर्थन मिलेगा तथा यह मजदूर वर्ग के आंदोलन के हित में एकता का एक प्रभावी मंच बन सकेगा.

कामरेड राममूर्ति ने केंद्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इंडस्ट्रिय फेडरेशनों को जो पत्र लिखा है वह इस तरह है.

"ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता और संयुक्त संघर्ष के सवाल ने बहुत ही खास अहमियत हासिल करली है. हमने मद्रास में संपन्न चौथे सम्मेलन में इस सवाल पर विस्तारपूर्वक विचार किया है. अभी हाल ही में हुए तमाम संयुक्त संघर्षों खास तौर पर औद्योगिक संबंध बिल के संदर्भ में हम महसूस करते हैं कि हम सब के सामने वह वक्त आ गया है जबकि मजदूर वर्ग तथा कर्मचारियों के संयुक्त आंदोलन को और ज्यादा व्यापक तथा मजबूत बनाने के लिए ट्रेड यूनियन आंदोलन के खास-खास मुद्दों पर आपसी विचार-विमर्श के लिए एक प्रभावी मंच के बारे में सोचा जाय.

हमारे संगठन के अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने चौथे सम्मेलन के समक्ष अपने अध्यक्षीय भाषण में सुझाव दिया था कि एक लचीले कनफैडरेशन की स्थापना की जाय या कम से कम आम सहमति तथा एकमत से फैसले लेने के लिए समस्त राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इंडस्ट्रियल फेडरेशनों की एक श्रम सम-न्वय समिति जैसे मंच का निर्माण किया जाय.

चौथे सम्मेलन में "मजदूर वर्ग के संयुक्त संघर्षों पर" भी एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया जिसमें राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इंडस्ट्रियल फेडरेशन के संयुक्त आंदोलनों के निर्माण के लिए यू. सी. टी यू. जैसे व्यापक संगठन के गठन का प्रस्ताव किया गया था.

हमें उम्मीद है कि आप ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता तथा संयुक्त संघर्ष की रक्षा के मसले में हमारे हम ख्याल बनेंगे.

हम आपसे निवेदन करते हैं कि राष्ट्रीय ट्रेड यूनियनों तथा इंडस्ट्रियल फेडरेशनों के कनफैडरेशन के गठन के हमारे प्रस्ताव के संदर्भ में अपने विचारों से हमें अवगत कराएं."

समूचे देश में अभूतपूर्व प्रदर्शन

सीटू द्वारा 9-10 अप्रैल को मद्रास में आयोजित अखिल भारतीय श्रमिक महिला सम्मेलन के, जिसमें 16 राज्यों से 440 डेलीगेटों ने भाग लिया था, के आह्वान पर समूचे देश में श्रमिक महिलाएं 30 मई को अपने कार्यस्थलों से बाहर आईं और अपने 20-सूत्री मांगपत्र के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शन, धरना और जुलूस आयोजित किए. मांग-पत्र स्थानीय अधिकारियों, श्रम आयुक्तों, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटों, मुख्य मंत्रियों और गवर्नरों को दिए गए. अनेक श्रमिक महिलाओं और उनके नेताओं ने सभाओं में उनकी मांगों और अधिकारों पर जोर देते हुए भाषण दिए.

पश्चिम बंगाल

30 मई को अखिल भारतीय श्रमिक महिला मांग दिवस समूचे पश्चिम बंगाल में मनाया गया. कलकत्ता के बाहर सभी जिलों और औद्योगिक केंद्रों में श्रमिक महिलाओं की सभाएं और प्रदर्शन आयोजित किए गए. कलकत्ता के एक हाल में एक सभा आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता पश्चिम बंगाल सरकार की समाज कल्याण मंत्री कामरेड निरूपमा चैटर्जी ने की. पश्चिम बंगाल सीटू के महासचिव कामरेड मनोरंजन राय, पश्चिम बंगाल के श्रम मंत्री कामरेड कृष्णपद घोष, पश्चिम बंगाल गणतांत्रिक महिला समिति के महासचिव कामरेड पंकज आचार्य, का. शिखा भट्टाचार्य, का. ऊमा मोइत्रा, का. प्रभा चैटर्जी आदि ने सभा में भाषण दिए. कामरेड मनोरंजन राय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में श्रमिक महिलाओं ने सभी जनवादी और राजनीतिक संघर्षों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है और ट्रेड यूनियन आंदोलन में भी प्रभावी भूमिका अदा करने में हमें उनकी मदद करनी चाहिए. कामरेड कृष्णपद घोष ने श्रमिक महिलाओं की समस्याओं पर जोर दिया और ट्रेड यूनियनों को उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेने का सुझाव दिया. कामरेड निरूपमा चैटर्जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि महिलाएं सामंती और पूंजीवादी शोषण से पीड़ित हैं अतः हमें सामंती और पूंजीवादी शोषण के खिलाफ भी लड़ाई लड़नी है. मजदूर वर्ग के सभी हिस्सों में श्रमिक महिलाओं के अखिल भारतीय मांग पत्र के प्रचार करने और इन मांगों के मनवाने के लिए समूचे टेड यूनियन आंदोलन को एकजुट करने का फैसला किया गया.

केरल

समूचे केरल के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक महिलाओं ने रैलियां और प्रदर्शन किए. दफ्तरों और फैक्ट्रियों में महिलाओं ने बिल्ले लगाए. कामरेड सुशीला गोपालन, देवकी वारियर, गिरिजा पोट्टी, निस्सिमा और कामरेड इंदिरा मुख्य मंत्री से मिलीं जिन्होंने बालगृह का इंतजाम करने और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों के ठीक प्रकार से लागू करने का वायदा किया. एर्नाकुलम और कोचीन में हाई कोर्ट के पास से एक जुलूस शुरू हुआ और बोटजेट्टी गया जहां पर कामरेड सरोजिनी बालानंदन, सोनी कामथ और अन्य ने भाषण दिए. त्रिचूर और कोझीकोडे व अन्य जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक महिलाओं ने प्रदर्शन किए और बिल्ले लगाए.

महाराष्ट्र

बंबई में, महिला कामगार कर्मचारी परिषद् ने सुबह 10 से शाम 4 बजे तक धरना आयोजित किया जिसमें 200 से भी ज्यादा श्रमिक महिलाओं ने भाग लिया. शाम को 4 बजे बीमा, टेलीफोन, नर्स, कपड़ा, ऊन व इंजीनियरी उद्योग की 3,000 से भी ज्यादा श्रमिक महिलाओं और महिला संगठनों की प्रतिनिधि जुलूस की शक्ल में धरने पर बैठी श्रमिक महिलाओं के साथ आ मिली. 4,000 से भी अधिक मांग दिवस के बिल्ले बांटे गए. सभा को कामरेड मृनाल गोरे, का. अहिल्या रांगणेकर, एम. पी., का. सुभाषिनी व अन्य ने संबोधित किया. वे महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री श्री शरद् पवार से मिलीं और एक ज्ञापन दिया. मांग-पत्र में सभी कार्यस्थलों पर बालगृह खोलने और सभी महिला खेत मजदूरों को 200 रुपये का प्रसूति भत्ता देने की मांग पर प्रकाश डाला गया. मुख्य मंत्री ने मांगों पर विचार करने और 10 जून को परिषद् के नुमाइंदों की एक बैठक बुलाने का वायदा किया.

दिल्ली

दिल्ली सीटू द्वारा आयोजित 400 से भी अधिक श्रमिक महिलाओं ने कश्मीरी गेट से एक जुलूस निकाला. इसमें पुरुष श्रमिक भी शामिल थे. यह जुलूस ओल्ड सेक्रेट्रियट गया. जुलूस में प्रदर्शनकारी लाल झंडे, फैस्टून, प्लेकार्ड —जिन पर श्रमिक महिलाओं की मांगें लिखी हुई थी, लिए हुए थे. आठ सदस्यीय डेलीगेशन, जिसमें अखिल भारतीय कमेटी की संयोजक कामरेड विमल रणदिवे, कामरेड बृंदा और दिल्ली सीटू के महासचिव कामरेड जयंत राय शामिल थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर (श्रम) से मिला और मांग पत्र दिया. एग्जीक्यूटिव काउंसिलर (श्रम) ने राज्य में श्रमिक महिलाओं की मांगों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाने का वायदा किया जिसमें सीटू की महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी. रैली में जन नाट्य मंच ने एक नाटक किया जिसमें महिलाओं की सम-

[शेष पृष्ठ तेरह पर]

रिजर्व बैंक कर्मचारी संघर्ष की राह पर

1974 में अखिल भारतीय बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन ने वेतन वृद्धि व अन्य मुद्दों के लिए एक मांग पत्र पेश किया. बैंक प्रबंधकों ने कारण बताए बिना इस पर विचार करने से भी मना कर दिया. इमरजेंसी के बहाने पर उन्होंने इसे अलमारी में बंद करके रख दिया. कर्मचारियों के संघर्ष और 1977 में हड़तालों कार्यवाहियों के कारण मुख्य श्रमआयुक्त (चीफ लेबर कमिश्नर) ने जनवरी 1978 में समझौता वार्ता शुरू की. प्रबंधकों के रवैये के कारण वार्ता 4 महीने तक रुकी रही. अंत में मई 1978 में प्रबंधकों ने अपना रुख बदला और मांग पत्र पर समझौता करने के लिए सहमत हुए. उनके यदि कोई भी मुद्दे होते तो उन पर केवल बाद में विचार हो सकता.

इस तरह मई और सितंबर 1978 के दौरान बातचीत के चार दौर चले. लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला —क्योंकि प्रबंधक इस बात पर अड़े हुए थे कि वेतन समझौता वार्ता के लिए कर्मचारियों को संशोधित मूल वेतन में कटौती और कम तथा कम होती हुई दर पर महंगाई भत्ते, जो एक हद के बाद स्थिर हो जाएगा, की पूर्व शर्त के तौर पर मानना होगा. एसोसिएशन द्वारा इन्हें मानने से इंकार करना स्वाभाविक ही था. बातचीत पूरी तरह ठप्प हो गई. इसके अलावा प्रबंधक पुनर्गठन व कंप्यूटर आदि की योजनाओं को लागू करने के लिए आगे बढ़ने लगे. इससे 6 मई 1978 को समझौते का पूरी तरह उल्लंघन किया गया.

कुछ महीनों बाद मुख्य श्रमायुक्त ने हस्तक्षेप किया, पिछले साल नवंबर व दिसंबर में बैठकें हुईं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला. कर्मचारियों में बढ़ता हुआ रोष 28 और 29 दिसंबर 1978 को हड़तालों व सभी दूसरे बैंक कर्मचारियों की इसी तरह की कार्यवाहियों में दिखाई पड़ा. केवल तब ही, 18 जनवरी 1979 को तीसरी बठक में, जिसमें मुख्य श्रमायुक्त भी हाजिर थे, 6 मई के समझौते का पालन करने के लिए माने और 27 जनवरी 1979 से मांग पत्र पर वार्ता शुरू की गई.

यह वार्ता नाकामयाब रही. वेतन के बारे में प्रबंधकों ने वही पुराना रवैया अपनाया और वे संशोधित मूल वेतन में कटौती व कम महंगाई भत्ते की दरों के लिए जोर देते रहे. जबकि पांच सालों से चली आ रही दूसरी मांगों के बारे में एसोसिएशन को 'परीक्षण किया जा रहा है', 'विचाराधीन है' आदि जवाब ही सुनने को मिले. दो और महीनों की टाल मटोल की नीति व एसोसिएशन के प्रति अपमानजनक व्यवहार ने कर्मचारियों की समूचे देश में रिज़र्व बैंकों में 3 अप्रैल को विरोध हड़ताल करने के लिए मजबूर किया. उसी दिन प्रबंधकों ने अपना रवैया बदला और बिना किसी पूर्वशर्त के समझौता वार्ता फिर से शुरू करने की इच्छा जाहिर की. एसोसिएशन इसके लिए तैयार हुई लेकिन बैंक प्रबंधकों का दोहरा चरित्र इतना साफ जाहिर था कि एसोसिएशन को इसके नतीजे के बारे में कोई गलतफहमी नहीं थी.

समझौता वार्ता का आखिरी दौर 2, 4 और 5 मई को चला. वेतन व दूसरे मुद्दों के प्रति प्रबंधकों के रवैये में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिला. प्रबंधक पूर्ण शर्तों पर अड़े रहे. सूचकांक (आधार 1960) के 200 प्वाइंट पर संशोधित वेतन में 10 प्रतिशत कटौती, मौजूदा महंगाई भत्ते की दरों में कमी और उसकी कम होती हुई दर, जो एक हद पर जाकर स्थिर की जाए, पेश की गई. इस तरह प्रबंधक कोई पूर्वशर्त न रखने के वायदे से मुकर गए. झसमता वार्ता टूट गई.

17,000 रिजर्व बैंक कर्मचारियों के पास अब कोई चारा नहीं रहा. जबरदस्त संघर्ष ही एक विकल्प बाकी था. जहां कहीं भी बैंक का दफ्तर है वहां पहले ही 16 मई से 'कोई ओवर टाइम काम नहीं', आंशिक तौर से काम रोक कर, मास डैप्यूटेशन आदि की कार्यवाहियां शुरू हो चुकी हैं. 21 मई से 'नियमानुसार काम' आंदोलन शुरू हो गया है. जाहिर है कि इसका असर बैंक के केवल पब्लिक काउंटरों तक ही सीमित नहीं रहेगा. करेंसी वितरण पर भी असर पड़ेगा. विभिन्न बैंकों से क्लीयरिंग हाउस द्वारा आदान प्रदान के काम अस्तव्यस्त हो जाएंगे. विदेशी मुद्रा नियंत्रण छिन्न भिन्न हो जाएगा. रिजर्व बैंक के काम के विभिन्न क्षेत्रों में काम रुक जाएगा. यह सब बैंक प्रबंधकों के औद्योगिक संबंधों के प्रति अड़ियल और प्राधिकारवादी रवैये के कारण ही होगा. आल इंडिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन के सेक्रेटरी कामरेड जी. के. भारद्वाज ने एक बयान में जनता को इससे होने वाली दिक्कतों के लिए खेद प्रकट किया है. उन्होंने कहा है कि हमारा संघर्ष आत्म-रक्षा और हमारे वेतन अधिकारों पर हमलों के खिलाफ है.

सहयोग के लिए धन्यवाद

सीटू के चौथे सम्मेलन के लिए तमिलनाडु में इक्ट्ठा किए गए चंदे का ब्यौरा :

मद्रास-चिंगलेपुट	रु.	48,887.00
कोयंबटोर-नीलगिरीज		40,519.00
मदुरई		14,941.00
साउथ अरकाट		13,289.00
नार्थ अरकाट		11,141.00
कन्याकुमारी		8,415.00
सालेम-धर्मपुरी		8,370.00
तिरूनेलवेली		4,037.00
तिरूची		3.867.25
तंजौर		2,740.00
रामानाद		2,047.00
पदुकोट्टई		983.00
कुल जोड़		1,59,186.25

दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों का संघर्ष

दिल्ली नगर निगम के 40,000 मजदूरों की फौरी मांगों को लेकर सीटू से संबद्ध म्युनिसिपल वर्कर्स लाल झंडा यूनियन ने ने 24 जनवरी को एक 22-सूत्री मांग-पत्र निगम अधिकारियों को दिया था. निगम के नौकरशाह अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण बातचीत द्वारा मांगों को हल करने के लिए यूनियन की कोशिशें नाकामयाब रही. इस लिए अपनी मांगों के समर्थन में 29 मई को सामूहिक अवकाश, टाउन हाल पर सामूहिक धरना तथा शहर में एक मौन जुलूस निकाल कर हजारों मजदूरों ने अपना विरोध जाहिर किया. इस में जल प्रदाय व सामान्य विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया. यूनियन द्वारा चेतावनी के तौर पर उठाए गए कदम के बावजूद यदि मांगें जल्द नही मानी गई तो संघर्ष और तेज किया जाएगा.

शोक समाचार

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के सदस्य और गाजियाबाद जिला कमेटी के सेक्रेटरी कामरेड नंदलाल मिश्रा का हाल ही में बीमारी के कारण देहांत हो गया. कामरेड मिश्रा गाजियाबाद सीटू के संस्थापक सदस्य थे. आप इमरजेंसी के खिलाफ लड़े और जेल गए. गाजियाबाद में आयोजित एक सभा ने कामरेड मिश्रा की असामयिक मृत्यु पर गहरा शोक प्रकट किया तथा उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना का इजहार किया.

झारिया कोलफील्ड में कोलियरी मजदूर सभा आफ इंडिया (सीटू) के सक्रिय कार्यकर्त्ता कामरेड सुधांशु की 11 मई को असामयिक मृत्यु पर 15 मई को पटना में एक सभा में गहरा शोक प्रकट किया गया.

केरल के श्रमिकों को सीटू की बधाई

औद्योगिक संबंध विधेयक, अध्यापकों के हड़ताल अधिकार पर पाबंदी और इंडैक्स कमेटी की सर्वसम्मत सिफारिशों के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घांघली को खत्म करने में राज्य सरकार की असफलता के खिलाफ तथा अन्य मांगों के समर्थन में एक दिन की प्रतिरोध हड़ताल करने के लिए केरल के मजदूरों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, प्रोफेसरों, खेत मजदूरों और सभी श्रमजीवियों का सीटू हार्दिक अभिनदंन करती है और उन्हें बधाई देती है.

ऐसी कार्यवाही पहले कभी देखने को नहीं मिली. इस अभूतपूर्व एकजुट संघर्ष से, जो यह दर्शाता है कि मजदूर वर्ग का एकजुट आंदोलन किस सीमा तक पहुंच सकता है, मजदूरों ने इतिहास की रचना की है.

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी.टी. रणदिवे ने 5 जून को एक बयान में कहा कि अधिकारियों को मजदूरों के मूड को नोट करना चाहिए और मजदूर वर्ग विरोधी कदमों को वापस लेना चाहिए तथा उनकी मांगें स्वीकार करनी चाहिए.

सीटूद्वारा एसोसिएटेड जरनल्ज के मजदूरों की मांग का समर्थन

सीटू के सेक्रेटरी, का० नृसिंह चक्रवर्ती ने 2 जून को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

सीट एसोसिएटिड जर्नल्स लि. के प्रबंधकों, नैशनल हेराल्ड, नवजीवन, अवामी आवाज (लखनऊ) वगैरह के प्रकाशकों की निंदा करती है क्योंकि उन्होंने तालाबंदी घोषित करके हजारों कर्मचारियों को बाहर निकालकर पटरी पर पहुंचा दिया है, उनका प्रोविडेंट फंड, बीमा, कर्मचारी राज्य बीमा निधि व आयकर कर्मचारियों के वेतन से काट लेने के बाद भी जमा न करके उन्हें धोखा दिया है. यह जानकर गहरा धक्का लगता है कि प्रबंधकों के इस निर्मम रवैये की वजह से ये सारे कर्मचारी भूखों मरने की हालत में हैं जबकि छः लोग अब तक भूख से मर चुके हैं क्योंकि पिछले चार महीने से कोई पैसा किसी को नहीं मिला है.

यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद में आश्वासन देने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे कर्मचारियों की तकलीफें कम हो सकें. न तो सरकार ने प्रबंध अपने हाथों में लिया है और न वह प्रबंधकों को तालाबंदी हटाने और वैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने पर मजबूर ही कर पायी है. यहां तक कि जब कर्मचारियों ने काम की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव किया तो सरकार ऐसे कदम उठाने के लिए आगे नहीं बढ़ी जिससे प्रबंध कर्मचारियों को सौंपा जा सके.

सीटू कर्मचारियों की मांगों का समर्थन करती है और सरकार से मांग करती हैं वह कर्मचारियों को प्रेस खोलने और काम करने का अवसर फौरन दे.

औद्योगिक संबंध बिल के खिलाफ संघर्ष और तेज किया जाएगा--राष्ट्रीय अभियान समिति

औद्योगिक संबंध बिल विरोधी राष्ट्रीय अभियान कमेटी की बैठक नयी दिल्ली में 6 मई, 1979 को हुई. कमेटी ने 19, नवंबर 78 को नयी दिल्ली में औद्योगिक संबंध बिल के विरोध में आयोजित अखिल भारतीय कनवेंशन के बाद के दिनों में राष्ट्रीय अभियान की स्थिति की समीक्षा की. कमेटी ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस अरसे में औद्योगिक संबंध बिल के विरुद्ध एकजुट होकर तमाम देश में अभियान चलाया है. इस अभियान के दौरान अनेक कनवेंशनों और रैलियों का आयोजन किया गया जिनमें मजदूरों ने भारी संख्या में भाग लिया. यहां तक कि शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों, सार्वजनिक ट्रस्टों और धर्मार्थ संस्थाओं के कर्मचारियों ने भी औद्योगिक संबंध बिल और उसके साथ के अन्य बिलों के विरोध में कार्यवाहियां कीं क्योंकि ये बिल उन्हें संगठन के अधिकार से वंचित करते हैं. इस देशव्यापी अभियान का नतीजा यह निकला कि सरकार अभी तक इस बिल की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ा पायी है.

राष्ट्रीय अभियान कमेटी ने उन सब लोगों को बधाई दी जिन्होंने इन बिलों की पूर्ण वापसी के लिए आवाज बुलंद की. उसने मजदूर वर्ग को आह्वान किया कि अंतिम रूप से इस बिल को वापस लौटाने तक वह अपने अभियान को और ज्यादा तेज करें.

राष्ट्रीय अभियान कमेटी ने यह भी फैसला किया कि नये औद्योगिक संबंध कानून में मजदूर वर्ग और तमाम देश के हितों को ध्यान में रखते हुए जो सुविधाएं होनी चाहिए उन्हें कमेटी संयुक्त रूप से देश के सामने रखेगी. इससे नवंबर 1978 में संपन्न अखिल भारतीय कनवेंशन के प्रस्ताव में जिन उद्देश्यों को सामने रखा गया था उनके अभियान में तेजी लाना और उनके लिए समर्थन हासिल करना मुमकिन होगा.

कमेटी ने इस व्यवस्था पर और गहराई से विचार करने के लिए 29 और 30 मई, 1979 को दिल्ली में फिर बैठक रखने का फैसला किया.

इस बैठक की अध्यक्षता एच. एम. एस. के अध्यक्ष एस. वेंकटरमन ने की और इसमें एच. एम. एस. सीटू, इंटक, एटक, बी. एम. एस., यू. टी. यू. सी. और यू. टी. यू. सी. (लेनिन सरणी) के नुमाइंदों ने भाग लिया.

राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और श्रमवीर राष्ट्रीय पुरस्कार योजनाएं

ये दो योजनाएं एक दशक से भी पहले बनाई गई थीं और ये केवल औपचारिकता बन गई. इस काम के लिए बनाई गई कमेटियों से सलाह लिए बगैर आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए और तय की गई गाइड लाइनों के अनुसार पुरस्कार दिए जाते रहे. 1977 से जब सीटू और अन्य ट्रेड यूनियनों के नुमाइंदों को कमेटी में शामिल किया गया तो योजना की पूरी समीक्षा की मांग की गई. कमेटी ने कई बार बैठक करने के बाद 29-30 मार्च 1979 की बैठक में योजना को तय किया. कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती, सचिव, ने सीटू का प्रतिनिधित्व, किया.

मुख्य परिवर्तन जिसे स्वीकार किया गया, प्लांट स्तर पर जहां से इन पुरस्कारों के लिए आवेदन आते हैं, संगठित श्रम की भागीदारी से ताल्लुक रखता है. यह भी माना गया कि ऐसे आवेदन प्लांट स्तर की सलाहकार कमेटी या सुरक्षा कमेटी से होकर आए और इन कमेटियों में बर्क्स कमेटी द्वारा नामांकित मजदूरों का एक प्रतिनिधि अवश्य हो, सीटू तथा एक अन्य केंद्रीय ट्रेड यूनियन ने सुझाव दिया कि यदि वर्क्स कमेटी न हो तो, मजदूरों का नुमाइंदा मजदूरों द्वारा गुप्तमतदान से चुना जाए. लेकिन अन्य इससे सहमत नहीं हुए.

सीटू ने यह भी सझाव दिया कि चयन वर्ष में जहां भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं या कोई पूरी तरह स्थायी तौर पर अयोग्य हो गया है तो उनको सुरक्षा पुरस्कार न दिया जाए, यह भी दूसरों ने स्वीकार नहीं किया. लेकिन यह सभी ने माना कि उन प्लाटों को जो सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के लिए दंडित किए गए तो उस साल उन्हें पुरस्कार पाने के अयोग्य किया जाएगा.

पुरस्कारों के मूल्यांकन व पुरस्कारों की राशि बढ़ाने आदि के भी उपयुक्त परिवर्तन किए गए. स्वास्थ्य दुर्घटनाओं व व्यावसायिक रोगों को भी एक उपयुक्त योजना के तहत प्रकाश में लाने के लिए भी शुरूआत हुई.

सुरक्षा नियमों के उल्लंघन, सुरक्षा कार्य, कर्मचारियों द्वारा नवीनीकरण आदि को प्रकाश में लाने के लिए प्लांट स्तर पर सीटू यूनियनों को पहल करनी चाहिए और यदि प्रबंधकों द्वारा कोई उल्लंघन के मामले सामने आएं तो उन्हें केंद्रीय कार्यालय को तुरंत सूचित करें.

सीटू मजदूर

सी आई टी यू का मासिक मुखपत्र
एक प्रति की दर पचास पैसे
वार्षिक चंदा छः रुपये
एजेंसी के लिए कम से कम पांच प्रतियां
मिलने का पता
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001

रेल कर्मचारियों और यात्रियों में एकता प्रयास

रेल द्वारा यात्रा करने वालों को, खास तौर से दैनिक यात्रियों को, रेलों के देर से चलने के कारण काफी दिक्कत उठानी पड़ती है. रेलों के देर से चलने के लिए पुराने यंत्र, जरूरी मरम्मत के लिए पुर्जों की कमी, रेल कर्मचारियों की संख्या कम करने की नीति आदि मुख्य कारण हैं. इसका फायदा उठाते हुए कुछ समाज विरोधी तत्व हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ईस्टर्न रेलवेमैंज यूनियन और ज्वाइंट काउंसिल आफ एक्शन, सियालदाह डिवीजन, की अगुवाई से रेल कर्मचारियों और दैनिक यात्रियों के बीच एकता बनाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया. पश्चिम बंगाल की वाममोर्चा सरकार के मुख्यमंत्री कामरेड ज्योति बसु, मुख्य वक्ता थे. सम्मेलन को पूरी सफलता मिली और यात्रियों को रेलों की देरी का कारण मालूम हुआ. रेलवे अधिकारियों की जनता और रेल कर्मचारियों को भिड़ाने की नीति नाकामयाब हुई.

रेल कर्मचारियों की कनफेडरेशन द्वारा नियमानुसार काम

वेतन समानता, बोनस आदि व दंडित करने वाले कदमों को वापस लेने की बुनियादी मांगों को स्वीकृत कराने के लिए रेल कर्मचारियों ने कंफेडरेशन के फैसले के मुताबिक डिवीजन और जोन स्तर पर कई सम्मेलन व प्रदर्शन किए तथा 19 अप्रैल को रेलमंत्री के निवास पर धरना दिया.

21 अप्रैल को समझौता वार्ता के दौरान रेल अधिकारियों ने मांगें स्वीकार करने से इंकार कर दिया और विक्टिमाइजेशन के मामलों को वापस लेने के लिए बहुत ही लज्जाजनक शर्तें रखीं जिसके कारण कार्यक्रमानुसार काम करने का आंदोलन शुरू करना पड़ा. हालांकि सरकार यह कह रही है कि इस आंदोलन का रेल सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन डाक/एक्सप्रैस/यात्री गाड़ियां देर से चल रही हैं, ढेर सारे पार्सल स्टेशनों पर पड़े हैं और कर्मचारियों को सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हुए काम करने के लिए धमकियां देकर मजबूर किया जा रहा है, पहले ही कुछ लोगों को मुअत्तिल किया जा चुका है.

हड़ताल सफल

सी. एल. डब्ल्यू. लेबर यूनियन के आह्वान पर 28 मार्च को चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में लगभग पूरी हड़ताल रही. ए. आई. आर. एफ. से संबद्ध यूनियन के एक हिस्से ने न केवल हड़ताल का विरोध किया बल्कि दंगा फिसाद करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया. हड़तालियों पर हमला बोल दिया जिसके विरोध में पूरी बस्ती ने उस दिन बंद आयोजित किया.

ए. आई. आर. एफ. द्वारा हड़ताल के लिए मतदान का फैसला

आल इंडिया रेलवेमैंज फेडरेशन (ए. आई. आर. एफ.) की जनरल काउंसिल ने नई दिल्ली में 8-9 मई को हुई बैठक में सभी संबद्ध यूनियनों को हड़ताल के लिए 31 अगस्त से पहले मतदान कराने के लिए निदेश दिए हैं. दिसंबर 1977 में 23-सूत्री मांग पत्र एक विशाल प्रदर्शन द्वारा दिया गया था जिस पर अभी तक कोई प्रगति नहीं हुए. इसलिए हड़ताल का फैसला किया जा रहा है. इस बार भी लगभग 20,000 रेल कर्मचारियों ने 7 मई को बोट क्लब पर प्रदर्शन किया और रैली को कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., और श्री जार्ज फर्नांडीस, उद्योगमंत्री, ने संबोधित किया.

जनरल काउंसिल ने ए. आई. आर. एफ. के महासचिव को अन्य बिरादराना रेल यूनियनों को अनुरोध करने के लिए कहा कि वे भी हड़ताल के लिए मतदान करें ताकि संघर्ष के दौरान एकता कायम हो सके. संबद्ध यूनियनों को भी इसी प्रकार से एकता के लिए कोशिश करने के लिए कहा गया. यह नोट करने की बात है कि एकता प्रयास पहले ही पूर्वी रीजन में शुरू हो चुके है और स्थानीय मांगों पर एकजुट आंदोलन के लिए फैसला लिया जा चुका है. एन. एफ. आई. आर ने बोनस और महंगाई भत्ते के लिए हड़ताल का दिन 31 मई से 31 जुलाई कर दिया है.

बी. आर. एम. एस. द्वारा मान्यता की मांग

8 मई को बी. आर. एम. एस. ने भी मान्यता और बोनस की मांग को लेकर बोट क्लब पर प्रदर्शन किया. 1977 में श्रम मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि मनमानी यूनियनों को मान्यता देना खत्म किया जाएगा और नया विधेयक आने से पहले सबको समान स्तर दिया जाएगा. लेकिन सरकार केवल दो फेडरेशनों को मान्यता की नीति ही अपनाए हुए हैं जब कि इस्पात, कोयला आदि के मंत्रालयों ने अपनी नीति बदल ली है. रेल मंत्री ने जनमत संग्रह का आश्वासन दिया है लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी अभी नहीं दी गई है.

रेलवे बोर्ड ने एल. आर. एस. ए. के. साथ हुए समझौते को लागू करने में देर की

पिछली मार्च में हुए समझौते को अभी तक लागू न किए जाने के बारे में ए. आइ. एल. आर. एस. ए. के महा-

[शेष पृष्ठ सात पर]

[पृष्ठ छः से आगे]

सचिव ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष को कई पत्र लिखे हैं.

इसी तरह की एक शिकायत ट्रेक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के महासचिव ने भी रेलवे बोर्ड के पास भेजी है.

दोनों ही ने 'नियमानुसार काम' आंदोलन में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अधिकारियों द्वारा दमनात्मक कदमों का विरोध किया है.

मीटिंग, कंनवेंशन आदि

ट्रेस्टर्न रेलवे सिगनल एंड टेली-कम्युनिकेशन स्टाफ एसोसिएशन का सालाना बैठक 28-29 अप्रैल को क्लेम ब्राउन इंस्टीच्यूट, सियालदाह, में हुई. इसका उद्घाटन कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., ने किया.

सी. एल. डब्ल्यू, लेबर यूनियन ने मई दिवस को एक विशाल रैली आयोजित की जिसमें कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., मुख्य वक्ता थे.

ट्रेक्शन वर्कर्स एसोसिएशन आफ साउथ ईस्टर्न रेलवे की सालाना बैठक 25-26 मई को आद्रा में हुई. आत्म रक्षा का औका दिए बिना डिवीजनल सचिव के निष्कासन और 175 से भी अधिक कर्मचारियों को विभिन्न तरीकों से दंडित करने के विरोध में प्रस्ताव पास किया गया.

जोनल कोआर्डिनेशन कमेटी आफ रेलवेमैंज ने 4 मई को खड़गपुर में सभी रेल कर्मचारियों का एक जोनल सम्मेलन किया. इसमें साउथ-ईस्टर्न रेलवे अधिकारियों से मांग पत्र के प्रति, जिसे छः महीने पहले दिया गया था, रवैये की कड़ी आलोचना कीग ई. सम्मेलन ने कंफैडरेशन के 'नियमानुसार काम' आंदोलन का समर्थन किया.

आल इंडिया स्टेशन मास्टर्ज एसोसिएशन की सालाना बैठक खड़गपुर में 27-29 मई को हुई जिसका कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., ने उद्घाटन किया.

रेल कर्मचारियों के खिलाफ क्षेत्रीय सेना के प्रयोग की सीटू द्वारा निंदा

सीटू के महासचिव व संसद सदस्य कामरेड पी. राममूर्ति ने 9 मई को निम्नलिखित बयान जारी किया है :

सीटू रेलवे मजदूरों के संघर्ष को कुचलने के लिए सरकार द्वारा क्षेत्रीय सेना (टैरिटोरियल आर्मी) के प्रयोग और विक्टिमाइजेशन की नीति की भर्त्सना करती है. एक ट्रेड यूनियन नेता के मंत्री होने के बावजूद रेलवे बोर्ड के नौकरशाहों द्वारा इस तरह की नीतियां काम में लाना आश्चर्य की बात है.

सीटू का यह दृढ़ मत है कि आल इंडिया रेलवे एंप्लाइज कनफैडरेशन द्वारा चलाये जा रहे 'नियम मुताबिक काम' के लिए रेलवे बोर्ड जिम्मेदार है. कनफैडरेशन ने अपने आंदोलन के कार्यक्रम की घोषणा फरवरी 1979 में ही कर दी थी. लेकिन यह जानते हुए भी रेलवे बोर्ड ने मजदूरों की न्यायसंगत मांगों को सुलझाने के लिए कोई प्रयास नहीं किये. इसके साथ ही 21 अप्रैल को बातचीत में कनफैडरेशन के नेताओं के साथ जो अपमानजनक रवैया बरता गया वह निंदनीय है.

बोनस तथा अन्य मांगों के लिए रेलवे मजदूरों ने 1974 में 20 दिन लंबा बहादुराना संघर्ष लड़ा था. बोनस के अलावा सभी स्तरों पर जमा होती गयी दूसरी समस्याओं के कारण पूरे देश में एक विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी. नौकरशाही ने उन्हें हल करने की बजाय अंधाधुंध विक्टिमाइजेशन का सहारा लिया. बोनस के सवाल पर भी रेलमंत्री के अनेक बार दुहराये गये आश्वासनों के अलावा कोई खास प्रगति नहीं हुई है.

सीटू सरकार को चेतावनी देती है कि यदि वह कांग्रेस सरकार के नक्शे कदम पर चलना छोड़ कर संघर्षरत मजदूरों से बातचीत नहीं शुरू करती तो रेल सेवाओं का सुचारू संचालन अस्त-व्यस्त हो सकता है. इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर होगी.

सीटू रेलवे मजदूरों के सभी हिस्सों से अपील करती है कि वे अपनी न्यायपूर्ण मांगों के लिए और विक्टिमाइजेशन की नीति का विरोध करने के लिए एकजुट हों. वह अपनी मांगों के समर्थन में संघर्षरत मजदूरों के हर संघर्ष के प्रति पूर्ण एकजुटता जाहिर करती है.

---

29 मई को पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार के श्रममंत्री कामरेड कृष्णपद घोष ने खुले अधिवेशन व विशाल रैली को संबोधित किया.

रेलवे ठेका मजदूरों का संघर्ष की तैयारी

रेलवे अधिकारी लोको शेडों व यार्डों में कोयला लादने या ढोने, पार्सल गाड़ी में चढ़ाने व उतारने, मीटर गेज से ब्राड गेज में डिब्बों को ले जाने और पुलों पर रंग करने आदि के स्थाई कामों को भी ठेका मजदूरों को दे रहे है, हालांकि कांट्रेक्ट लेबर (रैगुलेशन एंड एबोलिशन) कानून 1970 में बना था लेकिन उसे अभी तक अनेक अपीलों, विरोध आंदोलनों आदि के बावजूद भी लागू नहीं किया गया है. रेल मंत्रालय का कहना है कि जब तक सेंट्रल कांट्रेक्ट लेबर एडवाइजरी बोर्ड ठेके पर मजदूरों की भर्ती बंद करने का फैसला नहीं लेता है तब तक वह पुरानी नीति ही जारी रखेंगे. लेकिन दिसंबर 1977 बोर्ड में लोको शेडों और यार्डों में कोयला ढोने का काम ठेका मजदूरों को देना बंद करन के लिए सहमति के बावजूद भी अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है.

[शेष पृष्ठ दस पर]

दिल्ली के कपड़ा मजदूरों के साथ हर साल चार करोड़ रुपये की ठगी

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के गलत संकलन से दिल्ली के कपड़ा मिलों के 25,000 मजदूरों के साथ हर साल 4 करोड़ रुपयों की ठगी की जा रही है. इन कपड़ा मजदूरों को 1939 के सूचकांक के आधार पर महंगाई भत्ता दिया जाता है. और 1939 व 1960 के सूचकांकों में संबंध तय करने में घांधली के कारण मजदूर इतनी बड़ी मात्रा में धन से वंचित रहते हैं. 1960 के दिल्ली सूचकांकों 1939 के सूचकांकों में बदलने के लिए इस समय 4.38 से गुना किया जाता है. इसके लिए पहले 1960 के सूचकांक तय करके तब 1939 का निकाला जाता है. लेकिन यह गुणांक 4.38 गलत है और यह 5.85 से कम नहीं हो सकता. इस लिए अगर परिवर्तन गुणांक कम कर दिया जाए तो मजदूरों को महंगाई भत्ता कम मिलता है.

दिसंबर 1978 में 1960 की सीरीज का सूचकांक 369 प्वाइंट था और इसे 4.38 (मौजूदा परिवर्तन गुणांक) से से गुना करने से 1939 की सीरीज का सूचकांक 1618 प्वाइंट आता है. लेकिन इसे अगर 4.38 की बजाए 5.85 लिया जाए तो 1939 की सीरीज के तहत दिसंबर 1978 का सूचकांक 2159 प्वाइंट, यानि 541 प्वाइंट अधिक, आता है. और यदि ऐसा किया जाता तो दिल्ली के कपड़ा मजदूरों की 541 प्वाइंट के लिए 23 पैसे फी प्वाइंट की मौजूदा दर से महंगाई भत्ते के तौर पर रु. 124.43 और ज्यादा मिलते. महंगाई भत्ते में घांधली के कारण हर मजदूर से एक साल में रु. 1493.16 पैसे ठग लिए जाते हैं.

कलकत्ता औद्योगिक क्षेत्र में भी 1939 और 1960 के बीच परिवर्तन गुणांक में इसी तरह की घांधली थी. लेकिन सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के लंबे एकजुट संघर्ष के बाद एक छानबीन कमेटी बनाई गई जिसने मजदूरों के साथ कुछ न्याय करते हुए इस परिवर्तन गुणांक को 4.23 से 5.40 कर दिया.

सीटू से संबद्ध दिल्ली की कपड़ा मजदूर लाल झंडा यूनियन ने 1939 और 1960 की सीरीज के दिल्ली सूचकांकों में परिवर्तन गुणांक में संशोधन करने की मांग को उठाया है. आशा की जाती है कि दिल्ली के कपड़ा उद्योग में दूसरी यूनियनें इस मांग का समर्थन करेंगी और इस संशोधन के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगी.

कपड़ा मजदूरों की हड़ताल का समर्थन

कामरेड बी.टी. रणदिवे, अध्यक्ष सीटू, ने 27 मई को निम्नलिखित बयान जारी किया :

मैं तामिलनाडु के डेढ़ लाख कपड़ा मिल मजदूरों को वेतनवृद्धि और सेवाशर्तों में सुधार की मांगों को लेकर एकजुट होकर 25 मई से लगातार हड़ताल शुरू करने के लिए बधाई देता हूं.

तमिलनाडु के कपड़ा मजदूरों की मांगें बिल्कुल जायज हैं और और सीटू उनके सघर्ष का पूरा समर्थन करती है. पिछले कुछ सालों मे कपड़ा मिल मालिकों न भारी मुनाफा कमाया है और यह मुनाफा कच्ची कपास के दामों में मदी के कारण, जबकि कपड़े के दामों में कोई कमी नही आयी है, और भी बढ़ा. इसलिए मजदूरों की मागों को तय करने मे देरी का कोई कारण नही बनता.

सीटू तमिलनाडु के मिल मालिकों के रवैये की सख्त निंदा करती है और यह मांग करती है कि कण्ड़ा मजदूरों की वेतनवृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि और अन्य सेवा शर्तों में सुधार कि मांगें तुरंत मानी जायं.

सीटू इस तथ्य को गंभीरता से नोट करती है कि श्री. एम. जी. रामचन्द्रन के नेतृत्व में तमिलनाडु की राज्य सरकार ने जिसने इस मामले में कपड़ा मजदूरों के हित में हस्तक्षेप नही किया, पुलिस कानून की धारा 30(2) के तहत मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शनों और बैठकों के आयोजन पर पाबंदी लगा दी है. सीटू तमिलनाडु सरकार की इस मजदूर विरोधी नीति की सख्त अलोचना करती है और मांग करती है कि इस हड़ताल के समर्थन में प्रदर्शन और बैठकें करने पर सभी पाबन्दियों को तुरंत वापस लिया जाय और पुलिस की हड़ताल में दखलंदाजी को रोका जाय.

तमिलनाडु में कपड़ा मिलों की सभी यूनियनों ने यह हड़ताल सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर की है. इस एकता के लिए उन्हें बधाई देता हूं और हड़ताल को तब तक एकजुट हो जारी रखने का आह्वान करता हूं जब तक मांगे न मानी जायं.

रेल...

[पृष्ठ सात से आगे]

इन हालात में इंडियन रेलवेज कौंसिल एंड एश हेंडलिंग मजदूर यूनियन की दीनापुर, ईस्टर्न रेलवे 29-31 मई को हुई बैठक काफी महत्व रखती है. उनके आमंत्रण पर देश के विभिन्न केंद्रों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया. सीटू की बिहार राज्य कमेटी के सचिव कामरेड चंडी प्रसाद ने बैठक का उद्घाटन किया. देश के विभिन्न केंद्रों के प्रतिनिधियों ने संघर्ष की योजना बनाई. डेलीगेट सेशन खुले अधिवेशन तथा रैली में कामरेड समर मुखर्जी, एम. पी., और सीटू सचिव कामरेड नृसिंह चक्रवर्ती ने भाषण दिया.

आटो पिन्ज एंप्लाईज यूनियन, फरीदाबाद

सवा साल बाद भी मजदूरों का मनोबल बरकरार

आटो पिन्ज एंप्लाईज यूनियन का गठन फरीदाबाद कामगार यूनियन के तहत जनवरी 78 में हुआ था. फैक्ट्री के मालिकान के दमन व मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ लड़ने के लिए मजदूरों ने एक जुटता कायम की.

मजदूरों की तरफ से एक मांग-पत्र फैक्ट्री के प्रबन्धकों को 11 जनवरी 1978 को दिया गया था. प्रबन्धकों ने उस मांग पत्र पर कोई बात-चीत नहीं की. मजदूरों ने बार-बार प्रबन्धकों से अपील की थी कि आपसी समझौता किया जाए परन्तु प्रबन्धकों ने समझौता करने की बजाए मजदूर विरोधी रुख अपनाया. और 14 फरवरी 1978 को प्रबन्धकों ने फैक्ट्री के लग-भग 400 मजदूरों को स्थानीय पुलिस की सहायता से काम पर फैक्ट्री के अन्दर जाने से रोक कर ताला बन्दी कर दी.

मजदूर फैक्ट्री के बाहर 15 फरवरी को टैन्ट लगाकर शान्ति पूर्ण तरीके से मालिकान की मजदूर विरोधी नीतियों का विरोध प्रकट कर रहे थे उक्त फैक्ट्री के मालिक फैक्ट्री के अंदर आए. उन्होंने पहले से ही बाहरी गुन्डों को फ़ैक्ट्री के अन्दर पाल रखा था. उन गुन्डों ने फैक्ट्री के बाहर टैंट में बैठे हुए मजदूरों पर मालिक के इशारे पर अचानक घातक हमला बोल दिया. मजदूरों को इस प्रकार के हमले की आशंका भी न थी. गुन्डों ने मजदूरों पर लाठी, तलवार, बन्दूकों तथा अन्य घातक हथियारो से धावा बोला जिससे टैन्ट में बैठे मजदूर बुरी तरह घायल हो गए. परन्तु सबसे अफसोस की बात तो यह है कि जिस समय गुन्डों ने हमला बोला उस समय टैन्ट के पास सशस्त्र पुलिस खड़ी तमाशा देख रही थी. मजदूरों ने अपने बचाव के लिए पुलिस से सहायता मांगी परन्तु पुलिस कर्मचारियों ने पीठ फेर ली. किसी प्रकार घायल मजदूरों को अस्पताल में पहुंचा कर उनकी जान की रक्षा की जा सकी.

इस घटना की रिपोर्ट फरीदाबाद के डी. एस. पी., एस. एच. ओ. को तत्काल दी गई. परंतु पुलिस ने बजाए गुन्डों को गिरफ्तार करने के लगभग 200 मजदूरों को जबरदस्ती उनके घरों से, बजार से तथा रास्ता चलते पकड़ कर जेल में ठूस दिया और ऊपर से डन्डे भी बरसाए तथा बार-बार यह कहते रहे कि "देखा यूनियन का मजा कैसा होता है, अभी और भी भुगतना पड़ेगा". जेल के अंदर मजदूरों को न तो खाने का प्रबंध किया गया और न ही पानी का. जानवरों जैसा व्यवहार किया गया. 13 दिन की घिनौनी जल यात्रा करके मजदूर किसी प्रकार जमानत पर बाहर आए. पुलिस ने इ। के बाद भी मजदूरों के घरों पर जा कर उनके परिवार के साथ बुरा व्यवहार किया. लगभग 63 मजदूरों के अलावा और मजदूर केस से बरी भी हो गए.

उपरोक्त घटना की रिपोर्ट लेबर कमिश्नर महोदय को दी गई जिन्होंने मालिकान का पक्ष ले कर 24 फरवरी 78 के अपने पत्र में लिखा की मजदूरों की हड़ताल गैर कानूनी है. जब कि मजदूरों ने हड़ताल की ही नहीं. लेबर कमिश्नर महोदय के इस प्रकार से लिखने पर मालिकान का हौंसला बढ़ गया और वे किसी प्रकार के समझौते के लिए तैयार ही नहीं हुए.

सरकारी उच्च अधिकारियों तथा फैक्ट्री के मालिकान के इस प्रकार से मजदूर विरोधी नीति अपनाने पर मजदूरों ने भी यह कसम खाई कि "हम लोग सी. आई. टी. यू. की रहनुमाई में फैक्ट्री मालिकान के साथ तब तक लड़ेंगे जब तक दम में दम रहेगा चाहे हमें कितनी ही मुसीबतों का क्यों न सामना करना पड़े. मजदूर आज भी अपने वायदे मुताबिक मालिकान से लड़ने के लिए रिक्शा चला कर तथा दूसरी तरह जैसी तैसी नौकरी करके केस लड़ रहे हैं जब कि इस दौरान उन्हें तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. फैक्ट्री से बाहर हुए उन्हें लगभग 15 महीने हो गए परंतु वे अपनी प्रतीज्ञा पर अटल हैं.

सीटू द्वारा दिल्ली के कपड़ा मजदूरों के संघर्ष का समर्थन

सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी के जनरल सेक्रेटरी कामरेड जयंत राय ने 4 जून को एक बयान में कहा है कि सीटू की दिल्ली राज्य कमेटी दिल्ली के 25 हजार कपड़ा मजदूरों की अपनी वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में घांघली खत्म करने आदि की मांगों को मनवाने के लिए 27 जून से अनिश्चित-कालीन हड़ताल पर जाने के फैसले का पूरा समर्थन करती है. यह फैसला 3 जून को एक बड़ी कनवेंशन में लिया गया था जिसको सीटू, एटक, इंटक, बी. एम. एस. और एच. एम. एस. से संबद्ध यूनियनों व कुछ स्वतंत्र यूनियनों की एक संयुक्त संघर्ष समिति ने आयोजित किया था.

सीटू ने विभिन्न मिलों के प्रबंधकों द्वारा मजदूरों की मांगों के प्रति अपनाए गए अड़ियल व मजदूर विरोधी रवैये को नोट किया है और मांग की है कि प्रबंधक मजदूरों की मांगों को फौरन स्वीकार करें. सीटू ने कपड़ा मजदूरों को एकजुट संघर्ष के फैसले के लिए बधाई दी है और उन्हें पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है.

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों का कनवेंशन बंगलौर में

सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के वेतन आदि पर बातचीत चलती रही है. ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज इस बातचीत में अड़ंगा लगाने और टाल-मटोल करने का रवैया रखता आया है. 5 मई को नयी दिल्ली में आयोजित एक बैठक में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों ने ब्यूरो-अधिकारियों के इस रवैये के विरोध में बैठक का बहिष्कार किया. औद्योगिक संबंध विधेयक विरोधी राष्ट्रीय अभियान कमेटी में भाग लेने वाली केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों की 6 मई को अलग से हुई एक बैठक में इन मजदूर प्रतिनिधियों के इस कदम का स्वागत किया गया.

इस बैठक में इस बात पर भी गहरी चिंता व्यक्त की गयी कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 26 जून, 1978 को सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों को जो आश्वासन दिया था कि ब्यूरो आफ पब्लिक एंटरप्राइजेज वेतन की बातचीत में टांग नहीं अड़ायेगा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के साथ परामर्श करते हुए लचीली निर्देशक नीतियां तय कर ली जायेंगी, उनके इस आश्वासन पर अमल नहीं किया जा रहा है. इस बात को एक साल से ज्यादा हो गया लेकिन सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कारगर कदम नहीं उठाया. नतीजे के तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के कई संस्थानों में बातचीत रोक दी गयी है और विभिन्न उद्योगों में हड़ताल की तैयारी चल रही है.

बैठक में बंगलौर स्थित ट्रेड यूनियनों के इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया कि जून, 1979 के मध्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की यूनियनों का एक अखिल भारतीय कनवेंशन वहां आयोजित किया जाय. प्रस्तावित कनवेंशन में सारी स्थिति पर विचार किया जायगा और ऐसे कदमों पर फैसले लिए जायेंगे जिनकी मदद से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में मजदूरों का सामूहिक रूप से समझौता करने का निर्बाध अधिकार बना रहे और वेतन तथा महंगाई-भत्ते को रोकने की कोशिश को नाकाम किया जा सके.

बैठक ने बंगलौर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक उद्योगों की सभी ट्रेड यूनियनों को सलाह दी है कि वे एक व्यापक स्वागत समिति बनाएं और उसमें उस इलाके के सार्वजनिक उद्योगों की सभी ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ कर्नाटक राज्य में काम करने वाली सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की राज्य कमेटियों के प्रतिनिधियों को शामिल करें. बैठक ने सार्वजनिक उद्योगों की सभी ट्रेड यूनियनों से अपील की है कि इस बात की चिंता किये बगैर कि वे किसी केंद्रीय ट्रेड यूनियन से संबद्ध है या नहीं, वे इस कनवेंशन में अपने प्रतिनिधि भेजें और इसे शानदार ढंग से कामयाब बनाएं.

बैठक ने अपनी यह मांग दोहराते हुए, कि सभी मजदूरों को बोनस मिलना चाहिए, रेल, पी. एंड. टी. और रक्षा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा पिछले दिनों किये गये संघर्ष का समर्थन किया और उन्हें आश्वासन दिया कि अपनी न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए अगर वे भविष्य में ऐसा संघर्ष करेंगी तो ट्रेड यूनियन आंदोलन उन्हें पूरा समर्थन देगा.

इस बैठक की अध्यक्षता एम. एम. एस. के अध्यक्ष एस. वेंकटरमन ने की और इसमें एच. एम. एस., सीटू, इंटक, एटक, बी. एम. एस., यू. टी. यू. सी. यू. टी. यू. सी. (लेनिन सरणी) के नुमाइंदों ने भाग लिया.

सीटू द्वारा पंजाब में पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी की आलोचना

सीटू अध्यक्ष कामरेड बी. टी. रणदिवे ने 19 मई को यह बयान जारी किया है:

पंजाब में पुलिस-कर्मियों को फिर से गिरफ्तारी और उनके बर्बर दमन की आलोचना करती है. अखबारों में छपी रिपोर्टों के अनुसार एक हजार से भी ज्यादा संघर्ष करने के जुर्म में निकाल दिए गए हैं. वेतन वृद्धि करने में इतनी देरी ने, जबकि दाम बढ़ रहे हैं, पुलिस कर्मियों को संघर्ष का रास्ता अपनाने को मजबूर किया. इसकी पूरी जिम्मेदारी पंजाब सरकार पर हैं जिसने पुलिस बल की दिक्कतों के प्रति काफी लापरवाही की है. अब उनकी वेतन वृद्धि की मांग मान ली गई है, इसलिए उनको इसके लिए संघर्ष करने के लिए दंडित किया जाना बर्बरता है. सीटू पंजाब सरकार से गिरफ्तार किए गए सभी पुलिस कर्मियों को छोडने, सभी दमनकारी कदमों को वापस लेने, निकाले गए कर्मियों की नौकरी बहाल करने और पुलिस कर्मियों के साथ, जो बड़ी सहनशीलता के साथ जबरदस्त आर्थिक कठिनाइयों में रहे हैं' दुर्व्यवहार के भाव को कम करने की मांग करती है.

सीटू समझती है कि आम पुलिस कर्मियों की काफी दिक्कतें हैं जिन्हें उनकी एसोसिएशन द्वारा जो आई. पी. एस. अफसरों के नियंत्रण में हैं, प्रकाश मे नही लाया जाता और इसलिए अराजपत्रिक पुलिस कर्मियों को ट्रेड यूनियन अधिकार देना जनवादी सिद्धांत का एक हिस्सा है जिसे पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार ने माना है.

'दि वर्किंग क्लास'

एक प्रति की कीमत 50 पैसे
वार्षिक चंदा 6 रुपये

एजेंसी के लिए कम से कम 5 प्रतियां

लिखें : मैनेजर,
दि वर्किंग क्लास
6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : 384071

श्रमिक महिला मांग दिवस

[पृष्ठ दो से आगे]

स्थानों पर प्रकाश डाला गया था. फरीदाबाद में 25 श्रमिक महिलाओं और सीटू के पदाधिकारियों का एक डेलीगेशन एस. डी. एम. से मिला और मांग पत्र दिया. एस. डी. एम. ने मांग पत्र पर विचार करने के लिए सभी सहायक श्रम आयुक्तों की बैठक बुलाने का वायदा किया.

राजस्थान

जयपुर में 1,000 से भी ज्यादा श्रमिक महिलाएं इकट्ठी हुई और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाते हुए एक जुलूस निकाला. राजस्थान के गवर्नर को एक मांगपत्र दिया गया. राजस्थान में इस प्रकार की पहली रैली थी. मदनगंज-किशनगढ़ में प्रदर्शन किए गए. ब्यावर में 2,000 श्रमिक महिलाओं ने प्रदर्शन किया और स्थानीय अधिकारियों को मांग-पत्र दिया.

तमिलनाडु

तमिलनाडु में श्रमिक महिला मांग दिवस मनाने के लिए एक एक्शन कमेटी बनाई गई. इसने मद्रास में 26 मई को एक बैठक आयोजित की जिसमें 140 महिलाओं ने भाग लिया. बैठक के बाद एक जुलूस निकाला गया. 30 मई को केंद्रीय सरकार कर्मचारियों का एक दस सदस्यीय डेलीगेशन रीजनल लेबर कमिश्नर (केंद्रीय) से मिला. मांग-पत्र में श्रमिक महिलाओं के लिए ट्रांसपोर्ट के विशेष इंतजाम और श्रमिक महिलाओं के तबादले के समय उनकी दिक्कतों को मध्येनजर रखने की मांग पर प्रकाश डाला गया. 4,000 से भी अधिक पर्चे और 5,000 मांग बिल्ले बांटे गए. कैरी श्रमिकों (सीटू) ने एक धरना आयोजित किया जिसमें 52 महिलाओं ने भाग लिया और शाम को और महिलाएं उनके साथ आ मिली और प्रदर्शन किया. इससे पहले 28 मई को मद्रास के निकट पोन्नेरी तलुक के 5 गांवों से खेत श्रमिक महिलाएं जुलूस की शक्ल में आईं और तलुक आफिस के सामने प्रदर्शन किया.

उत्तर प्रदेश

कानपुर में प्रेस क्लब में अध्यापिकाओं, नर्सों, समाज सेवकों और फैक्ट्री श्रमिकों आदि की एक सभा की गई. एक चटकल मजदूर ने सभा में बताया कि उनके मिल में श्रमिक महिलाओं की संख्या 1950 में 300 थी जो घटकर अब 13 रह गई है. एक अध्यापिका ने बताया कि उन्हें तनख्वाह कम दी जाती है लेकिन दस्तखत ज्यादा पर कराए जाते हैं. यू. पी. राज्य सीटू के कोषाध्यक्ष कामरेड अरविंद कुमार ने महिला संगठन को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया. कामरेड देवसेना ने मांग-पत्र पढ़ा और 12 सदस्यों के एक डेलीगेशन ने इसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को दिया.

बंगलौर कनवेंशन अब जुलाई में

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों का अखिल भारतीय सम्मेलन अब जुलाई के तीसरे सप्ताह में बंगलौर में होगा. पहले यह 16 और 17 जून को होना था, लेकिन किन्हीं आवश्यक कारणों से इस फैसले को बदलना पड़ा है.

यह फैसला गत 29 मई को दिल्ली में हुई केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की बैठक में लिया गया. मीटिंग में सीटू, एच. एम. एस., एटक, बी. एम. एस., यू. टी. यू. सी., यू. टी. यू. सी. (लेनिन सरणी) के प्रतिनिधि उपस्थित थे.

बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की यूनियनों द्वारा का० के. एस. कृष्णमूर्ति के संयोजकत्व में एक स्वागत समिति गठित की गयी है.

सम्मेलन में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों की समस्याओं पर, मजदूरी निर्धारण के लिए चलने वाली बातचीत के दौरान सार्व-

[शेष पृष्ठ सोलह पर]

महंगाई के आंकड़े

(आधार 1960-100)

राज्य/केंद्र	1979		
	जन.	फर.	मार्च
बिहार			
जमशेदपुर	318	316	323
झारिया	314	312	316
कोडर्मा	341	340	341
मोंघाइर	338	340	340
नोआमुंडी	312	311	311
गुजरात			
अहमदाबाद	322	321	327
भाव नगर	336	334	335
हरियाणा			
यमुना नगर	357	356	362
जम्म व काश्मीर			
श्रीनगर	332	332	340
मध्य प्रदेश			
बालाघाट	355	353	355
भोपाल	335	366	336
ग्वालियर	346	342	355
इंदौर	356	356	358
महाराष्ट्र			
बंबई	324	323	236
नागपुर	328	324	324
शोलापुर	347	343	341
पंजाब			
अमृतसर	351	347	353
राजस्थान			
अजमेर	343	341	344
जयपुर	357	354	368
उत्तर प्रदेश			
कानपुर	336	334	335
सहारनपुर	344	342	344
वाराणसी	392	388	392
पश्चिम बंगाल			
आसन सोल	345	342	346
कलकत्ता	331	325	329
दार्जीलिंग	276	276	279
हावड़ा	321	317	321
जलपाइगुरी	273	273	282
रानीगंज	329	325	326
दिल्ली	368	368	371
भारत	332	329	332

(लेबर ब्यूरो, शिमला)

चौथे सीटू सम्मेलन को बिरादराना संदेश

फ्रांस

कामरेड पी. जेसाउस, सेक्रेटरी, कनफेडरेशन जनरल डु ट्रावेल, (सी. जी. टी.), पेरिस.

सी जी. टी. के कई लाख सदस्यों की ओर से कामरेड पी. जे साउस ने सीटू सम्मेलन को एक संदेश भेजकर सम्मेलन के डेलीगेटों की बधाई दी और इसकी सफलता की कामना की.

वियतनाम

फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस आफ वियतनाम, हनोई.

मौजूदा हालात के कारण फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस आफ वियतनाम कोई डेलीगेट नहीं भेज सकी. लेकिन इस फेडरेशन ने सीटू के चौथे सम्मेलन को एक संदेश भेजकर सम्मेलन के डेलीगेटों और भारतीय मजदूर वर्ग की भारतीय मजदूर वर्ग और जनता के आदर्श लक्ष्यों के लिए आंदोलन को आगे बढ़ाने में सफलता की कामना की है. वियतनाम मजदूर वर्ग और ट्रेड यूनियनों की ओर से इसने चौथे सम्मेलन के डेलीगेटों, भारतीय मजदूर वर्ग और सीटू से संबद्ध यूनियनों को बधाई दी हैं और उनके साथ वियतनामी मजदूरों और ट्रेड यूनियनों की एकता व मित्रता की कामना व्यक्त की हैं. संदेश में भारतीय मजदूरों और जनता के निर्वाह और जनवादी अधिकारों, अच्छे और सुखी जीवन तथा उन्नत भारत के लिए मजबूत और लगातार संघर्ष का समर्थन किया गया. वियतनाम पर चीनी हमले की भी आलोचना की गई.

सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतनाम के दूतावास के प्रथम सचिव, कामरेड हाजुय ने सम्मेलन में भाग लिया. उन्होंने वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन तथा समाजवादी वियतनाम के पुनर्निर्माण में मजदूर वर्ग की भूमिका के बारे में बताया. स्वतंत्रता के बाद वियतनाम में घटी खास-खास घटनाओं का भी कामरेड हाजुय ने उल्लेख किया.

कंपूचियन जनता द्वारा पाल पाट शासन पर विजय प्राप्ति और वियतनाम पर चीनी हमले के बारे में बताते हुए कामरेड हाजुय ने सम्मेलन को बताया कि 'ताजा समाचारों के अनुसार, सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतनाम की सरकार ने पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना की सरकार के साथ उप विदेश मंत्री स्तर पर 14 अप्रैल 1979 से हनोई में बातचीत करना स्वीकार कर लिया है उन्होंने आशा व्यक्त की कि पीकिंग शासक दोनों देशों के बीच विवादों को शांतिपूर्वक ढंग से सुलझाने के लिए बातचीत करेंगे.

सीटू के नेतृत्व में भारतीय मजदूर वर्ग के संघर्षों की प्रशंसा करते हुए कामरेड हाजुय ने कहा कि सीटू ने अतीत में राष्ट्रीय मुक्ति के लिए अमेरिका के खिलाफ हमारे प्रतिरोध और समाजवाद की रक्षा और उसके निर्माण के लिए हाल ही के संघर्ष का जो समर्थन किया है उसके लिए वियतनामी मजदूर वर्ग और जनता बहुत ही प्रभावित हुई है.

फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस आफ वियतनाम की ओर से सीटू और भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा उन्हें दिए गए समर्थन के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने सम्मेलन की हर सफलता की कामना की.

यूगोस्लाविया

काउंसिल आफ कनफेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंज आफ यूगोस्लाविया, बेलग्राद, यूगोस्लाविया.

कृपया निम्नलिखित संदेश सीटू सम्लेनन के डेलीगेटों को दें, प्रिय साथियो आपके चौथे सम्मेलन में भाग नही ले सकते. हम इस अवसर पर कनफेडरेशन आफ यूगोस्लाव ट्रेड यूनियंज की ओर से सम्मेलन के कार्यों की कामयाबी और भारत की बिरादराना जनता और मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए हार्दिक मैत्रीपूर्ण शुभकामनाएं भेजते हैं. हमें विश्वास है कि यह सम्मेलन भारत में मजदूरों की स्थिति को उभारने में एक और कदम होगा और आप द्वारा तय किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होगा. हम इस अवसर पर निर्गुट भारत और यूगोस्लाविया के मजदूरों के आपसी हितों के सभी मुद्दों पर एक बार फिर कनफेडरेशन आफ यूगोस्लाव ट्रेड यूनियंज और सीटू के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों व सहयोग के आगे विकास की कामना व्यक्त करते हैं.

चीन

आल चाइना फेडरेशन आफ ट्रेड यूनियंस. पीकिंग, पीपल्स रिपब्लिक चाइना

सीटू के चौथे सम्मेलन के अवसर पर हार्दिक बधाई. चीनी-भारतीय मजदूरों व जनता में परम्परागत मित्रता और हमारे ट्रेड यूनियन संगठनों में मित्रतापूर्ण संबंध लगातार बढ़ें और मजबूत हों.

कोरिया

सी. सी. जी. एच. टी यू., प्यांगयांग, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ कोरिया.

अपने संगठन के सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे ट्रेड यूनियंज डेलीगेशन को आमंत्रित करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपको सूचित करते हैं कि अनियंत्रण योग्य हालात के कारण हम अपना डेलीगेशन नही भेज सकते. बिरादराना शुभकामनाओं के साथ हम आपके सम्मेलन को बधाई देते हैं. और सम्मेलन कार्यों की और मजदूरों के जीवन हितों व जनवादी ताकतों की एकता के लिए आपके आगामी संघर्षों की सफलता की कामना करते हैं.

[शेष पृष्ठ पंद्रह पर]

बिरादराना संदेश...

[पृष्ठ चौदह से आगे]

यू. के.

लियोनेल मर्रे, महासचिव, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लंदन.

यूनाइटेड किंगडम में लगभग एक करोड़ बीस लाख ट्रेड यूनियनिस्टों की ओर से हम मद्रास, तमिलनाडु, में 11 से 15 अप्रैल 1979 को हो रहे सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियंज की चौथे सम्मेलन के डेलीगेटों को संबोधित करते है.

हमें आशा है कि आपका सम्मेलन आपके देश में पिछले कुछ सालों में हुए महत्वपूर्ण विकासों की समीक्षा करेगा, आपके संगठन और समूचे भारतीय ट्रेड यूनियन आंदोलन पर उनके प्रभाव का जायजा लेगा, और एक ऐसा संघर्ष कार्यक्रम तैयार करेगा जो मजदूरों को अपने प्रतिनिधि संगठनों के तहत राष्ट्रीय और रीजनल नीतियों को, जो उन्हें निर्वाह स्तरों व कार्य वातावरण की क्वालिटी के साथ काफी महत्ता के साथ जुड़ी होंगी, बनाने में और भी सक्रिय भूमिका अदा करने के लायक बनाएगा.

हम आपको अपनी शुभकामनाएं और बिरादराना बधाई देते हैं.

कामरेड प्रेम सिंह, नैशनल सेक्रेटरी, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन, ग्रेट ब्रिटेन, (हिन्दुस्तानी मजदूर सभा), डर्बी.

सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, लोकल एग्जीक्यूटिव कमेटी, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन की पूरी सदस्यता और भारतीय मूल के सभी मजदूरों की ओर से मद्रास में 11 से 15 अप्रैल 1979 को हो रहे सीटू के चौथे अखिल भारतीय सम्मेलन को अपनी हार्दिक, बिरादराना और क्रांतिकारी शुभकामनाएं भेजते हुए सम्मानित महसूस करती हैं.

आपका सम्मेलन बदले राजनीतिक हालात में हो रहा है—ऐसे हालात जिसमें कम से कम आपको खुले आम सम्मेलन आयोजित करने की इजाजत है. संशोधनवादी नेतृत्व द्वारा नियंत्रित एटक से अलग होने के बाद से ही सीटू भारत के मजदूर वर्ग के अनेक सामाजिक-आर्थिक और जनवादी संघर्षों का नेतृत्व करने में हमेशा आगे रही है.

सीटू मजदूर वर्ग जुझारू संगठन के रूप में, मजदूर वर्ग की मांगों के प्रति वास्तविक प्रतिबद्धता के साथ अनेक कठिनाइयों तथा मुसीबतों में काम करती रही है. जिस साहस और मुस्तैदी के साथ आपके संगठन ने श्रीमती गांधी के नेतृत्व वाले कांग्रेसी निजाम के खास-तौर पर एमर्जेंसी के दौरान दमन, आतंक तथा अनेक कामरेडों पर किये जाने वाले कातिलाना हमलों को सहा है, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है. आपके संगठन की त्याग और बलिदान की यह क्रांतिकारी परंपरा हमें जबरदस्त उत्साह और प्रेरणा देती है. ...और हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं कि भावी संघर्षों में हम हमेंशा आपके साथ एकजुट रहेंगे. क्रांतिकारी शुभकामनाओं के साथ.

श्री लंका

बेंटी वीराकूम, महासचिव, सीलोन फेडरेशन आफ लेबर, कोलंबो,

1975 में आपके पिछले सम्मेलन के बाद आपके संगठन और भारत के मजदूर वर्ग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों की समीक्षा करने के लिए एकत्र हुए डेलीगेटों को हम अपनी हार्दिक बिरादराना शुभकामनाएं भेजते हुए खुशी महसूस करते हैं. भारत में ट्रेड यूनियन और जनवादी अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट आंदोलन के निर्माण में सीटू की भूमिका को खास तौर से नोट करते हैं. बड़े संघर्षों के बाद भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा जीते गए अधिकारों को भारत सरकार द्वारा छीने जाने की कोशिशों के खिलाफ आपने जो एकजुट आंदोलन का निर्माण किया, उसने सरकार पर वांछित असर डाला जिसने सरकार की पार्लियामेंट में औद्योगिक संबंध विधेयक पेश करके जीते गए अधिकारों को छीनने की कोशिश को नाकामयाब कर दिया. साउथ एशिया में मजदूर वर्ग अधिकारों का छीना जाना नव उपनिवेशवादी कार्य है जिसने भारत और श्रीलंका की पूंजीवादी सरकारों पर असर डाला है. इस वास्तविकता को मध्येनजर रखते हुए सीलोन फेडरेशन आफ लेबर सरकार के इन कदमों के खिलाफ आंदोलन करने में कामयाब रहा है. यह आंदोलन सुरक्षात्मक प्रकृति का था लेकिन तो भी इसने सरकार पर असर डाला जिसने श्रम संबंधों के सिंघापुरी माडल पर एक कानून बनाने की कोशिश की थी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने हाल ही में हमारी एक शिकायत पर अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की है. यह रिपोर्ट सरकार के दोषों की साफ चित्रण हैं.

खतरा अभी टला नहीं है और ऐसी परिस्थितियों में आपके सम्मेलन में हमें हाजिर होना और हमारे कामन अनुभवों का अध्ययन करना. हमारे लिए महत्वपूर्ण होता. लेकिन हमें खेद है कि इस समय हम अपने सेक्रेट्रियट के किसी भी सदस्य को नही भेज सकते क्योंकि सरकार ने हाल ही में एक नया श्रम कानून पर्लियामेंट में पेश किया है और यह जरूरी है कि हम इसके बिना किसी देर के अध्ययन करें और अपनी राय कायम करें.

कृपया हमारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं स्वीकार करें.

भारतीय यूनियन

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आल इंडिया रिजर्व बैंक एंप्लाईज एसोसिएशन, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन, कन्फेडरेशन आफ सैंट्रल गवर्नमेंट एंप्लाईज यूनियन्स एंड एसोसिएशंज, आल इंडिया रेलवेमैंज फेडरेशन, आल इंडिया यूनिवर्सिटी एंप्लाईज कंफेडरेशन और भारतीय मजदूर संघ ने भी सम्मेलन को बधाई संदेश भेजे हैं.

Regd. No. D (C) 833

बंबई कपड़ा मजदूरों का नया वेतन समझौता

ग्रेटर बंबई के सूती कपड़ा मजदूरों ने अप्रैल 1979 में 45 रुपये की वेतनवृद्धि प्राप्त की है. 45 रुपये की इस वृद्धि पर महंगाई भत्ता नही दिया जाएगा और इसे केवल साधारण वृद्धि माना जाएगा. इसके अलावा जनवरी 1980 से मजदूरों को 6 रुपये साल की दर से सालाना वृद्धि आगामी 5 सालों तक दी जाएगी.

यह वेतन वृद्धि मजदूरों की उम्मीद से कहीं कम है. सूती कपड़ा मिल मालिकों ने पिछले सालों में काफी मुनाफा कमाया है और कपास के दामों में कमी के कारण उनके मुनाफे की दर और भी बढ़ गई है. इंटक यूनियन के, जिसने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, विश्वासघात के कारण मजदूरों को उचित वृद्धि नही मिली है.

बंबई औद्योगिक संबंध कानून के तहत, जिसे इंटक से सबंद्ध राष्ट्रीय मिल मजदूर सभा को ऊपर उठाने के लिए बनाया गया था, इंटक यूनियन ने सीटू सहित अन्य यूनियनों के एकजुट संघर्ष के फैसले को हतोत्साहित करने के लिए किया था.

ग्रेटर बंबई के कपड़ा उद्योग में हडताल की जबरदस्त तैयारियां चल रही थीं, मिल मालिकान की एसोसिएशन ने इंटक यूनियन की हड़ताल के फैसले को नाकाम करने के लिए इस्तेमाल किया. मजदूरों ने इस समझौते को इंटक द्वारा उनके हितों के साथ नया विश्वास-घात माना है.

हरियाणा पोलीस्टील्स

गैरकानूनी ढंग से मुअत्तल

हरियाणा पोलीस्टील्स लिमिटेड हिसार के प्रबंधकों ने 14 मई को 5 यूनियन नेताओं और 4 मजदूरों को बिना कोई कारण बताए गैरकानूनी ढंग से मुअत्तल कर दिया है. यूनियन की कार्यकारिणी की उसी दिन एक बैठक हुई और ट्रेड यूनियन नेताओं के विक्टिमाइजेशन के मामले को हरियाणा के मुख्यमंत्री और श्रम मंत्री तक ले जाने का फैसला किया.

बैठक ने सभी मजदूरों की तुरंत बहाली की मांग की और श्रम विभाग की मजदूरों के हितों की रक्षा करने में नाकामी की, हालांकि उसे समय से सूचित कर दिया था, कड़ी निंदा की.

सोनीपत सीटू के अध्यक्ष कामरेड जगर सिंह पर श्री चदंगी राम और उसके साथियों द्वारा हमले की सख्त आलोचना की और अपराधियों के बिरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की.

चौथे सीटू सम्मेलन के प्रकाशन

(अंग्रेजी में)

1. **दि सीटू रिजाल्व्ज इन मद्रास**
   [सम्मेलन की समीक्षा और प्रस्ताव] रु. 3 00

(हिंदी और अंग्रेजी में)

2. **अध्यक्षीय भाषण**
   —बी. टी. रणदिवे रु. 1.00
3. **महासचिव की रिपोर्ट**
   —पी. राममूर्ति रु. 0.75
4. **गतिविधियों और संगठन की रिपोर्ट**
   —एम. के. पंधे रु. 1.00

मिलने का पता :—

सीटू केंद्रीय कार्यालय,
6, तालकटोरा रोड,
नई दिल्ली 110001

कनवेंशन...

[पृष्ठ तेरह से आगे]

जनिक क्षेत्र के ब्यूरो द्वारा अत्यधिक हस्तक्षेप के बारे में, तथा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के समस्त कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते को मनमाने ढंग से निर्धारित करने के बारे में विचार किया जायगा और कर्मचारियों की मांगों को मनवाने के लिए संयुक्त संघर्ष के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जायगी.

संपादक मंडल

बी टी रणदिवे (अध्यक्ष)
पी राममूर्ति मनोरंजन राय
निरेन घोष सुधिन कुमार
एम के पंधे (संपादक)

एम के पंधे द्वारा सेंटर आफ इंडियन ट्रेड यूनियन्ज केलिए 6, तालकटोरा रोड, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और प्रोग्रेसिव प्रिंटर्स, 1,लारेंस रोड, रामपुरा, नई दिल्ली-110035 से मुद्रित) फोन 384071)